



उत्तराखण्ड शासन

ईमेल आईडी- info@ukmc.in
दूरभाष/फैक्स नं० 0135-2781201

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, श हीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

पत्रांक 574

दिनांक 16/9/2019

डॉ० आर०के०जैन, मा० अध्यक्ष, (मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2019 को पूर्वान्ह 10.30 बजे अल्पसंख्यक कल्याण भवन, श हीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून में आयोग की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त-

बैठक की उपस्थिति-

- 1-डॉ० आर०के०जैन, अध्यक्ष, (मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
- 2-श्री इकबाल सिंह, उपाध्यक्ष, (राज्य मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
- 3-श्री मजहर नईम नवाब, उपाध्यक्ष, (राज्य मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
- 4- श्री सुरेश चन्द जोशी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5-श्री रईस अहमद, उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- श्री रमेश लाल टम्टा, विधि अधिकारी, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण देहरादून।
- 7- श्रीमती सीमा जावेद, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
- 8- श्री गुलाम मुस्तफा, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
- 9- श्री अजगर अली, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
- 10- श्री राव काले खॉं, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
- 11-जे०एस०रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
- 12-श्री जगमोहन सोनी, मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा।
- 13-श्री शौकत अली, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० पिथौरागढ़।
- 14-श्री डी०एस०राजपूत, जिला शिक्षा अधिकारी चम्पावत।
- 15-श्री रणजीत सिंह नेगी, मुख्य शिक्षा अधिकारी अधिकारी ऊधमसिंहनगर के प्रतिनिधि।
- 16-श्री आर०सी० आर्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी।
- 17-श्री सी०एन०काला, मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 18-श्री एस०पी०सेमवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 19-श्री भास्कर नन्द पाण्डे, ब्लॉक खण्ड शिक्षा अधिकारी रामनगर नैनीताल।

बैठक में सर्वप्रथम मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों का परिचय करने उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2- बैठक में दिनांक 29.06.2019 की कार्यवाही के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर निराकरण न होने से खेद व्यक्त किया गया। इस सम्बन्ध में पुनः दिनांक 29.06.2019 की बैठक का कार्यवृत्त में दिये गये निर्देश के क्रम में एक माह अन्दर कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

3- बैठक में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के कम आवेदन पत्र प्राप्त होने की शिकायतों के सम्बन्ध में श्री रमेश लाल टम्टा विधि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं का पंजीकरण निरस्त हो चुका है। नये शैक्षणिक संस्थाओं के पंजीकरण के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है। वर्तमान में 1500 शैक्षणिक संस्थाएँ ही पंजीकृत हुए हैं। इस सम्बन्ध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश किया जाता है कि अपने अधीनस्थ जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को ऑन-लाईन हेतु पंजीकरण के सम्बन्ध में निर्देशित करें, व 10 दिन के अन्दर अनुपालन से निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड व उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग को अवगत करायें, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी छात्रवृत्ति हेतु पात्र अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएँ छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहियें। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, उपस्थित नहीं हुए, इस सम्बन्ध में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा से अपेक्षा है कि अनुपस्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मा0 आयोग को अवगत करायेंगे। छात्रवृत्ति की जांच हेतु सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 556(1) / XVII-3/2017 दिनांक 29, मार्च, 2017 के द्वारा प्रदेश में वितरित अल्पसंख्यकों की वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की छात्रवृत्ति की जांच के निर्देश दिये गये थे, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, के द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत की गयी थी, अन्य जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा शासन के उक्त पत्र का अनुपालन नहीं किया गया, 15 दिन के अन्दर वर्णित पत्र में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन करते हुए निदेश क, अल्पसंख्यक कल्याण व मा0 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग को अवगत कराया जाय। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून को भी निर्देशित किया जाता है कि अल्पसंख्यक कल्याण से सम्बन्धित समस्त छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने स्तर से भी समय-2 पर निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही-महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून,
निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून व समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड)

4- प्रदेश में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को घोषित करने की प्रायः शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस सम्बन्ध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएँ घोषित किये जाने हेतु अपने स्तर से तत्काल प्रकरण का



निस्तारण करना सुनिश्चित करे, साथ ही यह भी निर्देश किया जाता है कि अपने-2 जनपद से सम्बन्धित समस्त घोषित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण करते हुए यह अवगत कराये कि उन शैक्षणिक संस्थाओं में मानकों के अनुसार अल्पसंख्यक छात्र-छात्राये अध्ययनरत है, यदि जिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राये अध्ययनरत नहीं है, तो उन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को रखे जाने का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव यथशीघ्र एक माह अन्दर मा0 आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड)

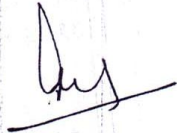
5. बैठक में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में संचालित कतिपय मदरसों में मिड-डे मील की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद से सम्बन्धित समस्त मदरसों का समय-2 पर निरीक्षण करवाये, व मदरसों की समस्या भी सुनी जाये, व मदरसों का पठन-पाठन कार्य सुदृढ़ किया जाय। उसका एक वार्षिक प्रत्यावेदन तैयार कर उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड)

6 बैठक में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रदेश के समस्त जनपदों में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाये, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्त योजनाओं की जानकारी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को दी जाये, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी व ब्लॉक स्तर से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी अल्पसंख्यक कल्याण जनजागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना दी जाये। बैठक का संचालन सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा की जाय। बैठक में उपाध्यक्षगण व सम्बन्धित जिले के सदस्य के द्वारा भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेगा। सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग कार्यक्रम हेतु पृथक से कार्यालय ज्ञाप जारी करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड व समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी)

7- अल्पसंख्यक कल्याण भवन में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा पानी की बंद प्लास्टिक बोतल व अन्य प्रकार से पौलीथिन को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये गये, इसके साथ ही सम्पूर्ण भवन को स्वच्छ एवं साफ रखा जाय,। निदेशक, अल्पसंख्यक



कल्याण को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से भी निर्देश जारी कराते हुए अनुपालन कराया जाय।

(कार्यवाही- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून)

8- पूर्व में भी सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदस्तर, विकासखण्ड स्तर, तहसील एवं थाने आदि स्तर पर उनका सम्मान नहीं किया जाता है, यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व भी निर्देश जारी किये गये थे। पुनः समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा है कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यगण के भ्रमण कार्यक्रम में सम्मान दिये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, /पुलिस अधीक्षक उत्तराखण्ड)

9- पूर्व में भी निर्देशित किया गया व पुनः बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश निर्देश दिये गये उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं० 166/XXVII(7)/2008 दिनांक 29, अप्रैल, 2008 के अनुसार अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया, इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक आयोग को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी कार्यवाही चाहे व जनता की शिकायत हो, अथवा मा० अल्पसंख्यक आयोग के (मा० उपाध्यक्ष/सदस्यगण) सुझाव व अन्य कार्यवाही हो, बिना अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी प्रकार से सचिव, अल्पसंख्यक आयोग अपने स्तर से कार्यवाही नहीं करेंगे। सभी कार्यवाही सचिव, अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुमति के पश्चात् ही कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही- सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग)

10- बैठक में मा० आयोग के सभी सदस्यगणों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उनका मानदेय रू० 6000/- मासिक है, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की भांति मानदेय 6000/- के स्थान पर 25000/- बढ़ाये जाने हेतु मा० मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, पूर्व में भी मा० आयोग के द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया था। इस सम्बन्ध में भी सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण से अपेक्षा है कि मा० आयोग के सदस्यगणों का मासिक मानदेय रू० 6000/- के स्थान पर रू० 25000/- करने की कार्यवाही करते हुए मा० आयोग को अवगत करायें।

(कार्यवाही- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन)



अतः में बैठक में अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरः अनुपाल कराये जाने की अपेक्षा के साथ सभी प्रतिभागी गणों का सधन्यवाद ज्ञापित करते हु बैठक समाप्त की गयी।

ह0/-
(डॉ0 आर0के0जैन)
अध्यक्ष

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

पत्रांक 574 /उ0अ0स0/बैठक-कार्यवृत्त/2019-20 दिनांक 16,सितम्बर 2019

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2- निजी सचिव, मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित
- 3- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तराखण्ड।
- 6- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर।
- 9- बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण।
- 10- गार्ड फाईल।


(जे0एस0रावत)
सचिव

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।